सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

<u>संख्या–818</u> **बिहार के अनुरूप नक्सली उग्रवाद का निदान समेकित विकास से ही सम्भव**

14–7–2010

<u>श्री नीतीश कुमार।</u>

दिल्ली 14 जुलाईः– श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार ने कहा है कि वामपंथ उग्रवाद के समस्या का समाधान केवल सुरक्षा बलों के माध्यम से अभियान चलाने से व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता। नक्सली तत्व भी हमारे ही समाज के अंग हैं, जिन्हे हिंसा का रास्ता चुनने के लिए प्रेरित कर दिया गया है। सुरक्षा बलों के बूते पर नियंत्रित करने के प्रयास मात्र से नक्सली संगठनों के नेताओं को हीरो बनने का मौका मिल जाता है, जब की सतही निदान के अभाव में उन्हे तीव्र गति से हिंसा फैलाने का मौका मिल जाता है। इस समस्या के स्थायी निदान हेतु बिहार द्वारा अपना गया समेकित दृश्टिकोण एक प्रभावी और स्थायी निदान के लिए उपयुक्त रणनीति कही जा सकती है।

श्री कुमार आज प्रधानमंत्री निवास में वामपंथी उग्रवाद पर आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। श्री कुमार ने कहा कि यद्यपि की बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए ''आपकी सरकार आपके द्वार'' एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रही है। हमारी रणनीति विकास एवं कल्याण की योजनाओं को अपने लक्ष्य तक पहुँचाने के पूर्व सुरक्षा भी प्रदान करने की है। योजना आयोग द्वारा ऐसे क्षेत्रों में विकास योजनाओं को लागू करने की पहल एक सराहनीय कदम है। बिहार सरकार अपने नागरिकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा के साथ मानवधिकारों की रक्षा करते हुए कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार को इस प्रयास में अच्छी सफलता मिली है। श्री कुमार ने बिहार में विगत् दस वर्शों का आँकड़ा प्रस्तुत कर राज्य सरकार की रणनीति के प्रभावी परिणाम की ओर ध्यान आकृश्ट किया। श्री कुमार ने संतोश जताया कि ये सारी उपलब्धियाँ बिना मानवाधिकरों के हनन के शिकायत मिले प्राप्त हुआ है। श्री कुमार ने कहा कि राज्य में कार्यबल, हथियारों और संसाधनों की कमी के बावजूद हमने नक्सली समस्या पर नियंत्रण में सफलता पायी है।

मुख्यमंत्री श्री कुमार ने बताया कि वे स्वयं अगस्त तक कुल बारह हजार सिपाही की रीक्तियों को भरने के लिए केन्द्रीय सिपाही भर्ती बोर्ड की समीक्षा कर रहे हैं, पिछले वर्श बहाल दो हजार पुलिस अवर निरीक्षकों को प्रशिक्षित कर जिलों में तैनात कर दिया गया है, राज्य सरकार ने राज्य पुलिस बल को आंतरिक उग्रवाद का सामना करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु सी0आई0ए0टी0 विधालयों के संचालन के लिए यद्ध स्तर पर कार्य प्रारम्भ कर दिया है। राज्य सरकार ने राज्य में दो सौ करोड़ की लागत से पुलिस एकेडमी स्थापित की है। उन्होंने बताया कि इस अंतरिम अवधि में दो हजार राज्य पुलिस बल के जवानों ने उग्रवाद विरोधी, जंगल–युद्ध बी0एस0एफ0 सेना एवं अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

श्री कुमार ने कहा कि कुछ खास तथ्यों के समुचित समाधान हेतु मैं प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृश्ट करना चाहता हूँ। राज्य सरकार द्वारा नक्सल समस्या को देखते हुए केन्दीय अर्द्धसैनिक बलों की मांग बार–बार करने के बावजूद विगत् कई वर्शों से केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की संख्या में कोई परिवर्तन नही किया गया। विगत् 8 अक्टूबर 2009 को सम्पन्न बैठक के उपरान्त दूसरे राज्यों में केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में बढ़ोतरी की गई, जबकि बिहार को एक भी अतिरिक्त कंपनी मुहैया नहीं

कराया गया। पुलिस मुख्यालय, बिहार के स्तर से विशिश्ट उपकरणों के लिए किए गए अनुरोध पर प्राथिमिकता के आधार पर गृह मंत्रालय द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है।

श्री कुमार ने कहा कि इस बैठक के कार्यावली से ज्ञात होता है कि देश में कुल 83 वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिले हैं। कुल 35 मात्र जिलों में समेकित विकास के लिए योजना आयोग को समेकित कार्य योजना तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। भोश 48 जिले तो पिछड़े ही रह जायेंगे फिर अधिकांश जिलों को छोड़ने से समस्या का हल कैसे सम्भव है? श्री कुमार ने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि चयनित 35 जिलों में 6 जिले बिहार राज्य के भी हैं। श्री कुमार ने कहा कि उग्रवाद प्रभावित जिलों में समेकित विकास की आवश्यकता को बिहार ने बहुत पहले ही भांप लिया और ''आपकी सरकार आपके द्वार'' कार्यक्रम 8 जिलों के 65 उग्रवाद प्रभावित पंचायतों में प्रारम्भ कर दिया। राज्य सरकार का यह कार्यक्रम सुरक्षा के साथ विकास का एक केन्द्र विन्दु बन गया है। इस कार्यक्रम के तहत इन्दिरा आवास योजना, विद्यालय भवन एवं ग्रामीण सड़कों के अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएँ चलाई गई है ताकि चुने हुए पंचायतों में विकासात्मक गतिविधियाँ पूर्णतया संतृप्त हो सके और जरूरत मंदों को इस कार्यक्रमों के सारे लाभ उन्हे उनके दरवाजे पर ही मिल सके। उन्होने स्मरण दिलाया कि आंतरिक सुरक्षा पर विगत् 7.2.2010 को नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की सम्पन्न बैठक में भी उन्होंने इस कार्यक्रमों को चलाने के लिए केन्द्रीय आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की थी। पुनः मैं अपनी मांग दूहराता हूँ।

मुख्यमंत्री श्री कुमार ने बताया कि बिहार के 33 वामपंथ जिलों में से 15 जिलों को एस0आर0ई0 योजना में भाामिल किया गया है। मात्र 5 और जिलों को इस योजना में भाामिल करने संबंधी अनुरोध पर अभी तक गृहमंत्रालय अपनी सहमति प्रदान नही की है। बावजूद इसके राज्य सरकार अपने बल बुते पर स्थिति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है।

श्री कुमार ने कहा कि आज की बैठक के कार्यवली विन्दुओं के तहत 33 उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए प्रमुख योजनाओं में विमुक्त राशि के व्यय का प्रतिशत वार तालिका भी है। जहाँ तक बिहार से संबंधित अंकित विवरणों का प्रश्न है यह अलग ही एक कहानी है। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार केन्द्रीय विभिन्न मंत्रालयों के उदासीन रवैये का शिकार रहा है। वित्तीय वर्श– 2009–10 नरेगा श्रम बजट के तहत बिहार के लिए 3259 करोड़ का प्रावधान था, जबकि केन्द्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2010 तक मात्र 36 प्रतिशत अर्थात् 1033 करोड़ ही विमुक्त किया गया। 31 मार्च 2010 तक केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मात्र 147 करोड़ विमुक्त की गई। चूँकि बहुत पंचायतों में राशि समाप्त हो गई थी फलस्वरूप बारम्बार अनुरोध के बावजूद आवंटन में एक बड़ा अन्तराल ब्याप्त रहा। आधिकांश जिलों ने केन्द्रीय राशि के लिए व्यय विवरणी एवं राज्य सरकार की अनुशंसा भेंज दी थी। इस विशम परिस्थिति के बावजूद हमने 1818 करोड़ रु० ब्यय किया, जो पिछले वित्तीय वर्श की अपेक्षा 40 प्रति ात अधिक है।

श्री कुमार ने अन्त में कहा कि मेरा विश्वास है कि वामपंथ उग्रवाद की समस्या का समाधान निरन्तर विकास के माध्यम से ही किया जा सकता है। बिहार जैसे प्रदेश जहाँ उच्च स्तर की पहल एवं प्रतिबद्धता विकास की कमियों को दूर करने के लिए तो है, परन्तु संसाधन की भारी कमी है, के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समुचित सहायता प्रदान करने की दृश्टिकोण अपनाना पड़ेगा।

सम्पन्न सम्मेलन की अध्यक्षता डा० मनमोहन सिंह, प्रधान मंत्री ने की केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री पी0 चिदम्बरम, केन्द्रीय रक्षा मंत्री, श्री ए0के0 एनटोनी, केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी सहित उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्य मंत्रियों एवं केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया।

————————